GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 219
ANSWERED ON MARCH 16, 2021

MEASURES TO CURB INFLATION DUE TO SHORT SUPPLY OF ESSENTIAL COMMODITIES

219. SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government has planned any measures to reduce the inflation due to short supply of essential commodities – vegetables, cereals, etc. because of natural calamities; and

(b) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI ANURAG SINGH THAKUR)

(a) to (b): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 219 BY SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR DUE FOR ANSWER ON MARCH 16, 2021

.....

(a) and (b): Government takes various measures from time to time to stabilize prices of essential food items which, inter-alia, include appropriately utilizing trade and fiscal policy instruments like import duty, minimum export price, export restrictions, etc. to regulate domestic availability and moderate prices; imposition of stock limits and advising States for effective action against hoarders and black marketers; and, provision of higher minimum support prices to incentivize farmers for increasing production. Government is also implementing Schemes which, inter alia, include Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), National Food Security Mission (NFSM), National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP), etc for increasing agricultural production and productivity through appropriate interventions. Government also implements Price Stabilization Fund (PSF) to help moderate the volatility in prices of agri-horticultural commodities through buffer of pulses namely Urad, Gram, Tur, Moong, and Masoor as well as buffer of onion. The main objective of the buffer is to release the stock in a calibrated manner to moderate price volatility and thereby mitigate hardships to the consumer. Further, the retail and wholesale prices of 22 essential commodities are being monitored on a daily basis. The prices situation and trends are analysed to provide inputs for decision regarding release from buffer and the import-export policy etc.

*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 219

(जिसका उत्तर, सोमवार, 16 मार्च, 2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

आवश्यक वस्तुओं की कम आपूर्ति के कारण होने वाली महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय

219. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण सब्जियों, अनाज इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कम आपूर्ति से होने वाली महंगाई को कम करने के लिए कोई उपाय किए जाने की योजना बनायी है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री जी.सी. चन्द्रशेखर द्वारा पूछे गए दिनांक 16 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 219 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमत को स्थिर करने के लिए समय-समय पर कई उपाय करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात प्रतिबंध, स्टॉक सीमा लागू करना तथा घरेलू उपलब्धता एवं संतुलित कीमतों के विनियमन हेतु जमाखोरों तथा कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राज्यों को सलाह जैसे व्यापार और राजकोषीय नीति लिखतों को समुचित रूप से उपयोग करना और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक समर्थन मूल्य की व्यवस्था करना शामिल हैं। सरकार योजनाओं को भी लागू कर रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, उपयुक्त हस्तक्षेपों के माध्यम से कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बागवानी का एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पाम ऑयल (एनएमओओपी) आदि शामिल है। सरकार उड़द, चना, तूर, मूंग और मसूर नामक दलहनों के बफर तथा प्याज के बफर के माध्यम से कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को कम करने में मदद करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) को भी कार्यान्वित कर रही है। बफर का मुख्य उद्देश्य मूल्य अस्थिरता को कम करने के लिए अंशांकित रीति से स्टॉक को जारी करती है और जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता की कठिनाइयां कम होती हैं। इसके अतिरिक्त, 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा और थोक कीमतों की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है। बफर से जारी करने और आयात-निर्यात नीति के संबंध में निर्णय करने के लिए इनपुट प्रदान करने हेतु कीमतों की स्थिति और रुझानों का विश्लेषण किया जाता है।

*****

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, there has been rise in prices of essential commodities. For example, there has been hike in the price of LPG cylinder from Rs. 204 to Rs. 840; there has been a hike in the prices of black gram from Rs. 98 to Rs. 200, per kilogram; a hike in the prices of green gram from Rs. 414 to Rs. 1,136, per kilogram; a hike in the prices of onions from Rs. 3,127 to around Rs. 4,500, per quintal; a hike in the prices of potatoes from Rs. 1,000 to Rs. 2,300, per quintal. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief and put your question. ...(*Interruptions*)...
SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Similarly, Sir, there has been a hike in the prices of cooking oil from Rs. 80 to Rs. 150. Even the steel prices have been hiked to Rs. 63,000, per ton.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question, please.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, can't the Government bring this under the Price Monitoring Division of essential commodities? When the people are facing so many difficulties in earning their livelihood, how can the common people survive?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are supposed to put a specific question.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, the food items in the Consumer Food Price Index are showing a month-on-month decline. If you look at the CFPI, there has been a decline of 0.58 per cent from January to February. The cereals have declined by 0.14 per cent; meat and fish have declined by 1.01 per cent; eggs have declined by 3.54 per cent; vegetables have declined by 3.50 per cent; and, pulses have declined by 0.19 per cent. Apart from that, there is a Price Stabilization Fund. We had started that in 2015. But, in 2019-20, the allocation was close to Rs. 1,713 crores, which had been spent. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No interruptions, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: You gave a long list of items. I have given only a very small list of items where the prices have come down on month-on-month basis.

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप चेयर को संबोधित करें।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, the Price Stabilization Fund for the Consumer Affairs Ministry has been given. In the BE stage for 2020 and 2021, it was Rs. 2,000 crores. But, looking at the COVID situation and the situation arisen out of it, it was increased to Rs. 11, 800 crores at the RE stage. In this year's Budget also, a sum of Rs. 2,700 crores has been earmarked for the Price Stabilization Fund.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, the hike in fuel prices has added additional burden on the Transport Departments of all the States. In my State, an employee of the Transport Department went to sell his kidney due to the unavailability of salary. Also, the food inflation fell by 1.89 per cent to twenty months' low. When will the inflation come down? Will the Government take immediate action on this?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सरकार के पिछले सात वर्षों में महंगाई दर औसतन कम रही है, जितनी रहनी चाहिए, उसके आस-पास ही रही है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुओं के कारण, जिनकी सप्लाई में कमी हो, कोविड के टाइम पर वह कमी देखने को मिली - डिमांड ज्यादा बढ़ी उसके कारण भी। लेकिन इसके बावजूद हमने एमएसपी के दाम जहां पर किसानों के लिए बढ़ाए, तो हिन्दुस्तान में दलहन, तिलहन का उत्पादन ज्यादा बढ़ा, इम्पोर्ट भी कम करना पड़ा - जहां हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत थी, हमने वह भी किया। और पैसे को भी बढ़ाया है, ताकि दामों को स्थिर रखा जा सके, वे ज्यादा न बढ़ें। वर्ष 2013-14 में या उस समय में double digit inflation था, आजकल यह उसके मुकाबले में कम है, लेकिन सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि महंगाई को और कम किया जाए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने महंगाई कम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बताया है। अभी यह देखने को मिला है कि जो किसानों के बिल आए थे, उनमें आपने किसानों की उपज के लिए unlimited stock के लिए अनुमति दे दी है, इसीलिए पूरे देश में किसान धरने पर बैठा।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें न बढ़ें, उनके कंट्रोल के लिए क्या आप लिमिट निधारित करेंगे, क्या आप कृषि बिल में संशोधन करवाएंगे?

श्री उपसभापति : यह प्रश्न उससे संबंधित नहीं है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, इसका उस प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार ने stock करने की अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं, चाहे वह onion की हों या pulses की हों। सर, इसके लिए क्यों है? सर, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि pulses की जो stock करने की capacity

थी, वह साढ़े उन्नीस लाख मीट्रिक टन थी। उसको बढ़ाकर तेईस लाख मीट्रिक टन किया गया, ताकि अगर कहीं पर दालों की कमी होती है, तो वह आपके अनाज भंडार में इतनी हो, ताकि कोई दाम बढ़ा न सके। सर, buffer stock के लिए भी निर्धारित किया गया कि कोई इसको stock न कर सके। हमारी सरकार के आने के बाद चाहे राज्यों में भी कहीं कोई कमी है, तो हमने उनको निर्देश देकर कहा कि वहां पर कोई भी दालों का भंडारण न करे, कालाबाजारी न करे। यही एक बड़ा कदम था कि कई लोगों को उसका भुगतान भी करना पड़ा।

श्रीमती कान्ता कर्दम : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या केन्द्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण सब्जियों या अनाज आदि की कम आपूर्ति से होने वाली महंगाई को कम करने के लिए इन वस्तुओं का निरंतर आयात करने की योजना बना रही है? क्या ऐसे .....

श्री उपसभापति : धन्यवाद, केवल एक ही क्वेश्चन पूछिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा प्रयास यह है कि हमारे देश के किसानों ने अपनी मेहनत से हमारे अनाज के भंडार भरे हैं। हमने उनके लिए MSP के दाम पिछले सात वर्षों में लगातार बढ़ाए हैं और हम आगे भी किसानों की आय को दुगना करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे भंडार भरे रहें, इसके लिए हमने लगातार प्रयास किया है, ताकि कोई भी कमी बाज़ार में न आए। अगर आप 2009 से 2014 के बीच में देखेंगे, जहां average inflation rate 10 से 12 प्रतिशत रहता था, वहीं 2014 से 2019 के बीच में चार, साढ़े चार परसेंट महंगाई की दर रही है। एक बड़ा कारण यह भी था कि सरकार ने एक तरफ अपने किसानों की क्षमता बढ़ाई तो दूसरी तरफ किसानों ने मेहनत करके अनाज के भंडार भरे। सर, जो दालें बहुत बड़ी मात्रा में import की जाती थीं, आज उनका उत्पादन यहां पर किया जाता है। यदि ऑयल सीड्स की बात हो- तो पाम ऑयल भी जो import किया जाता है, हमने उसकी ड्यूटी भी कम की है। दूसरी ओर एक ऐसा प्रोग्राम भी चलाया है, ताकि हमारी क्षमता स्थानीय स्तर पर बढ़ सके। ये सारे कदम इसी दिशा में उठाए जा रहे हैं, ताकि महंगाई कंट्रोल हो और हमारे किसानों की आय भी दुगनी हो।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर : डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि point फिगर का नहीं है, point stock का नहीं है, आज़ादी के बाद से आज तक गरीब आदमी की जरूरत तेल और दाल रही है। अभी तक देश में इसकी पैदावार कम होती है। क्या आप उनको assured MSP देंगे, ताकि जो देश में दिक्कत है, वह भी खत्म हो और रेट भी सस्ते हों। इसके साथ ही जो देश का पैसा बाहर जाता है, वह भी बचेगा और किसान तरक्की करेंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, माननीय सांसद बहुत सीनियर मेम्बर हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना खेती का और संसद का लम्बा अनुभव देखेंगे, तो आपके ध्यान में यह आएगा कि MSP के दाम अगर record बढ़ाए हैं - मैं आपको लम्बी लिस्ट पढ़कर बता सकता

हूं - उसके बाद भी कारण क्या हैं। जब दलहन-तिलहन का दाम बढ़ा, समर्थन मूल्य बढ़ा तभी हमारे देश के किसानों ने दलहन-तिलहन की तरफ ध्यान दिया तो इनका आयात भी कम हुआ है। यह काम पिछले 6-7 वर्षों में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के समय में हुआ है। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा, हम किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास करते रहेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over. The House stands adjourned till 2.00 p.m.